We are only talking about Subash Chandra Bose. I request everybody to sit down now and I will call other persons.

SHRI V. GOPALSAMY: I respect the observations of the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is very nice of you.

SHRI V. GOPALSAMY : When a Member of Parliament expresses his opinion about Netaji, I am also entitled to express my opinion. *(Interruptions).*

THE DEPUTY CHAIRMAN : If he has said anything which is controversial, it will not be on record. Mr. Bhubaneswar Kalita, if I allow you, then I have to allow everybody.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam) : Madam, just one point. It is very important. While associating myself with the sentiments expressed by my friend, Shri S.S.Ahlu-walia, I want to say one thing. Madam there is a systematic design in that part of the country of belittling the freedom movement and damaging the status of our national leaders. It is not the only case. There have been other cases also. I request the Government to strengthen the Central Intelligence agencies. They are very poorly manned and have poor information. Recently, we have seen how a defence convoy was attacked by the terrorists and 23 people were killed. This shows how poor is the defence information, how poor-es the information of the Central Intelligence agencies working over there. Through you, Madam, I request the Government to strengthen the Central Intelligence agencies there so that before these incidents take place and before these damages are done, they can take some precaution. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Dr. Abrar Ahmed, as a Parliamentary Affairs Minister, kindly convey the sentiments of the House to the Government. I mean, whatever sentiments have been expressed here regardless of the parties and by the Chair also, the feelings about what happened to the statue of Netaji Subhash Chandra Bose and whatever suggestions have come, the Government should examine them and whatever best they can do, they should do.

Plight of Indian/Hajis in Saudi Arabia During the Haj Celebration of 1993

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मैं आपके सामने इस साल जो हाजियों का मसला है, वह रखना चाहता हूं।

मैडम, मेरे जिम्मे राज्य सभा से यह जिम्मेदारी मुझको दी गई है कि मुझे राज्य सभा की तरफ से हज कमेटी का मेम्बर नामिनेट किया गया था, जिससे मैंने 14 जून को इस्तीफा दे दिया।

मैडम, मैंने हज कमेटी से इस्तीफा देते वक्त चेयरमैन साहब को खत लिखा था। मैं उम्मीद यह करता था कि हुकूमत, जो मैंने चीजें उठाई हैं, उस पर गौर करेगी।

मैडम, इस साल हाजियों की जो दुर्गति बनी मक्का में, खास तौर पर वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिये, हज कमेटी एक अहमतरीन इदारा है, जो हिंदुस्तान के 25 हजार हाजियों को यहां से ले जाने और वहां उनके इंतजामात की जिम्मेदारी निभाती है। इस पर हर साल कुछ न कुछ क्रिटिसिज्म होता रहता है। पिछले तीन साल से मैं भी इसका मेम्बर था और पिछले तीन साल से मैं सऊदी अरब बराबर जा रहा था।

मैडम, यह बहुत ही सेंसेटिव मजहबी मसला है मुसलमानों का और मैं इसके लिए कोई बात कहने से पहले, हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं और मैंने पहले भी ऐसा किया है कि आज तक

हिंदुस्तान में जो भी सरकार आई है, उस सरकार ने इस मसले को टाप प्रायर्टी पर इसके मसायल को हल करने की कोशिश की है और मुकम्मल कोआपरेशन दी है। मैं इस मौके पर जो हमारे मिनिस्टर आफ स्टेट फार फारेन अफेयर्ज, आर. एल. भाटिया साहब हैं, मैं खास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि गुजिश्ता एक साल में उन्होंने जो कोआपरेशन हज कमेटी और हाजियों के लिए दी है, मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं, वह कम है। मैंने गुजिश्ता उससे दो साल पहले उतना कोआपरेशन नहीं देखा।

इसलिए, जो आज मैं खड़ा होकर कह रहा हूं, मेरी शिकायत हुकूमते-हिंद से नहीं है। मुझे सच्ची बात कहनी चाहिए, क्योंकि यह बड़ा मुक्कदस-फरीज़ा है—इसके अंदर में किसी को गलत बात नहीं कहना चाहता हूं। हज कमेटी वह जिम्मेदार इदारा है, जो हाजियों से पैसे लेकर उनको हवाई-जहाज से ले जाने और वहां पर अकामोडेशन का इंतजाम करती है, और उसमें शर्त यह होती है कि जब हाजी यहां से जाए, तो उसको हम हरम-शरीफ से, यानी एक्च्युअल प्लेस आफ वरशिप जो है, वहां से चार सौ-आठ सौ मीटर की दूरी पर रहने के लिए जगह दें।

लेकिन इस साल ऐसे हालात पैदा हुए कि कांट्रैक्ट एक प्राइवेट पार्टी से किया गया। इससे पहले यह कांट्रैक्ट सऊदी अरब का एक डिपार्टमेंट है मोससा उसके जरिए से हम वहां अकामोडेशन का इंतजाम करते थे।

इस साल हमारी हज कमेटी का जो डेलीगेशन गया, उसने कुछ हालात की बुनियाद पर एक प्राइवेट पार्टी से कांट्रैक्ट किया। जब हमारा हाजी यहां से रवाना हो गया, उसके दो महीने बाद कांट्रैक्ट के, तो सऊदी गवर्नमेंट से एक मैसेज हमारी फारेन मिनिस्ट्री को मिला कि आपके हाजी पहुंचने से पहले, हज कमेटी आये और हमसे बात करे। यहां से एक डेलीगेशन गया, जिसमें फारेन मिनिस्ट्री के ओ.एस.डी., हज, भी शामिल थे मैं भी शामिल था और आज एक्स-चेयरमैन हैं वह भी शामिल थे। हम वहां गए। हमें सऊदी मिनिस्टर साहब के सामने बैठने का मौका मिला। यह 4 अप्रैल की बात है, उन्होंने हमको बताया और 5 अप्रैल को हमारा शिप तकरीबन डेढ़ हजार हाजियों को ले करके वहां पहुंचने वाला था। उन्होंने कहा कि यह कांट्रैक्ट आपने इलीगल किया है और आपको किसी प्राइवेट पार्टी से यह कांट्रैक्ट करने का हक नहीं है। आप कांट्रैक्ट डाइरेक्ट लैंडलार्ड से तो कर सकते हैं, लेकिन बीच में किसी एजेंट को ले करके यह कांट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैडम, हमारी दरख्वास्त र हज मिनिस्टर ने, उन्होंने कह दिया था कि यह इलीगल कांट्रैक्ट है। लेकिन हम 8 करोड़ रुपया उस प्राइवेट मेंबर को पे कर चुके थे और वह हाजियों की अमानत था हमारे पास और हमें उस 8 करोड़ की बड़ी फिक्र थी। लिहाजा हमने हज मिनिस्टर के आगे हाथ जोड़े। मैंने खुद हाथ जोड़े और यह कहा कि अगर यह बाय चांस गलती भी हुई है तो हमको यह मौका दिया जाए, हमारा हाजी कल आ रहा है, हम कैसे उसको करेंगे मैं सऊदी गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूं खास तौर पर उन मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने इसके बावजूद कोआपरेट किया और कोआपरेट करने के बाद हाजियों का इंतजाम किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैडम, हाजियों को वह इंतजाम इस साल हम नहीं दे सके, जो हाजी का हक बनता है जो वह हमें 50 हजार रुपये की एक खतीर रकम अदा करते वक्त वह हम से एक्सपैक्ट करता है, जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर शायद होती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि

हर काम के लिए हज कमेटी खतावार है। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जो एम्बैसी है, एम्बैसी की बात कर रहा हूं, मैं कौंसिल जनरल की बात नहीं कर रहा हूं, एम्बैसी जो है और खास तौर पर एम्बैसेडर जो हैं इशरत अजीज साहब... (व्यवधान)

उपसभापति : जो लोग यहां अपने को डिफेंड नहीं कर सकते, उनका नाम मत लीजिए और थोड़ा जल्दी कीजिए।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मडम, मैं एम्बैसी की बात करूंगा कि उसने वह कोआपरेशन नहीं दिया जो उसका फर्ज बनता था। इसके नतीजे में हाजियों को सख्त परेशानी हुई और उसके नतीजे में मैंने यह महसूस किया कि इसमें चाहे गलती किसी भी भी हो जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर हज कमेटी की है। चूंकि मैं भी हज कमेटी का एक मैंबर हूं और मैडम, उससे ज्यादा शर्मनाक बात हज का मामला और अखबार में दिल्ली के अन्दर यह छपा और फिर उसके बाद पूरे हिन्दुस्तान के अदर छपा कि हज कमेटी के कुछ लोगों ने करोड़ों रुपये की रिश्वत एकोमोडेशन के अन्दर ले ली। मैडम, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर हज कमेटी के किसी मैंबर ने रिश्वत ली थी तो क्या हकूमत का यह फर्ज नहीं है कि उसकी तहकीक करे? इसलिए कि हम पब्लिक मैन हैं। अगर मेरी हज कमेटी के किसी मैंबर के ऊपर रिश्वत का इल्जाम लगता है तो मैं अपने आपको उससे बरी उस समय करार नहीं दे सकता। मैं तो उसी दिन जिस दिन यह, पहले दिन यह अखबार में खबर छपी कि हज कमेटी के किसी मैंबर ने रिश्वत ली है, अगर यह खबर झूठी थी तब भी मैं इस्तीफा दे देता। लेकिन मैंने इस लिहाज से इस्तीफा नहीं दिया कि अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो एक हैवक क्रिएट हो जाएगा। हाजियों का हमारे जाना शुरू होने वाला था। अगर मैं उस वक्त इस्तीफा देता तो एक हैवक क्रिएट हो जाता और हंगामा खड़ा हो जाता, हाजियों को बहुत सख्त परेशानी होती। लिहाजा मैंने उस वक्त अपने आपको रोका और मैं खुद सऊदी अरब इस बार गया। जाकरके जो मैंने अपनी आंखों से हाजियों की दुर्दशा देखी है, मैडम, आप जानती हैं अच्छी तरह से क्योंकि आपका ताल्लुक भी उसी कम्युनिटी से है कि एक हाजी मक्के के अंदर खड़ा हो करके कभी किसी को बद दुआ नहीं दे सकता। ...(व्यवधान) लेकिन हरम शरीफ के नीचे हाजियों ने इस तरह से खड़े हो कर हज कमेटी के मेंबरान को बद दुआएं दीं तो मैंने यह सोचा कि मेरा इस कमेटी में रहना ठीक नहीं है। कमेटी चाहे मुकम्मल तौर पर इसके लिए जिम्मेदार न हो, लेकिन मैं यह समझता हूं कि पैसा हम लेते हैं हाजी से, बेचारे गरीब हाजी को यह पता नहीं है कि यहां क्या पोलिटिक्स है। किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर हज कमेटी की है। इसलिए मैंने अपना इख्लाकी फरीजा समझा कि उससे इस्तीफा दे दिया।

पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे इस्तीफे का क्या हुआ? क्या मेरा इस्तीफा एक्सैप्ट हुआ था नहीं? क्योंकि कल दोबारा हज कमेटी की मीटिंग हो रही है। मैडम, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने वजीरे खारजा को ....(व्यवधान) नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ...(व्यवधान) मैं तो जानना चाहता हूं कि डेढ़ महीना हो गया (व्यवधान).. मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मैंने....(व्यवधान)

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह (महाराष्ट्र) : फिर आपको कल की मीटिंग की क्या परेशानी है?

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : विश्वजित जी, मैं कुछ बात इससे रिलेटेड कहना चाह रहा हूं, आप सुन तो लें।

उपसभापति : अफजल साहब, आप थोड़ा सा संक्षप में बोलें तो मेहरबानी होगी।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने यह डिमांड की थी दूसरी जो परेशानी हाजियों को हुई वह एअर लाईन्स के सिलसिले में हुई थी। इस बार एअर इंडिया ने यह कह दिया कि हमारे पास जहाज नहीं है। इंडियन एअर लाईन्स ने हमारे हाजियों को ले जाने से इन्कार कर दिया और एअर इंडिया को इंतहाई जल्दी के अंदर एयरो-फ्लोट के कुछ एअरक्राफ्ट लीज पर लेने पड़े और उनसे कांट्रैक्ट किया। मैडम, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारा यह फर्ज नहीं है, हम एअर इंडिया के सबसे बड़े क्लाइंट हैं यानी हाजी, हम 34 करोड़ रुपए के टिकिट खरीदते हैं, तो क्या यह फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाना चाहिए? क्या एअर इंडिया की यह ड्यूटी नहीं है कि वह यह सारा जो ट्राफिक है, खुद हैंडल करे ताकि यह हमारा पैसा मुल्क में मौजूद रहे? आज हमने एअरो फ्लोट को जो टिकिट का पैसा फॉरेन एक्सचेंज में दिया, क्या जरूरत थी इसे बाहर भेजने की? इसलिए मैंने यह डिमांड की थी जब मैंने वजीरे खारजा को यह खत लिखा था कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को वह कहें कि वह ऐसा इंतजाम करें कि हमारा नेशनल कैरियर खुद हाजियों को लेकर जाए और हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाया ना हो। तीसरी डिमांड मैडम मैंने यह की थी कि इस हज कमेटी को फौरन तोड़ दिया जाए क्योंकि इस हज कमेटी के ऊपर आवाम का एतमात खत्म हो चुका है और मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया है हालांकि मुझे भाटिया साहब ने खत लिखा है कि कमेटी रिकांस्टीट्यूट कर रहे हैं। मैडम, आखिरी एक बात मैं यह कहना चाहता हूं जोकि मैंने एक साल पहले भी उठायी थी और आप उसकी खुद गवाह हैं और मैं समझता हूं कि चेंबर के अंदर आप उसूली तौर पर मुझसे एग्री करती थी, जिस वक्त मैं मेंबर था उस वक्त मेरी मौजूदगी में, जबकि मैं मेंबर था हज कमेटी का, एक मेंबर को आनेवाली कमेटी के लिए मेंबर नामजद कर दिया गया था जोकि उसूली तौर पर गलत बात थी। मैंने एहतराज किया था और यह भी कहा था कि अगर इस तरह से किसी मेंबर को अपमानित करने की कोशिश की जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन मैंने उस वक्त इस बात को ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं बनाया था। अब कमेटी रिकांस्टीट्यूट होने वाली है और मैंने चेयरमैन साहब को आज ही खत लिखा है कि जो अपाइंटमेंट पहले किया गया था वह गलत था, वह रूल के खिलाफ था। यह हमारी परंपरा नहीं रही है इसलिए आप उस नाम को वापिस लीजिए और जिसको बेहतर समझें उसको हज कमेटी के अंदर नोमीनेट करें, लेकिन एक साल पहले जो अपाइंटमेंट किया गया है या नोमीनेशन भेजा गया है, वह गलत है।

इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

شری محمد افضل عرف م افضل (اتر پردیش): میڈم، میں آپ کے سامنے اس سال جو حاجیوں کا مسئلہ ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔

میرے ذمہ راجیہ سبھا سے یہ ذمہ داری مجھ کو دی گئی ہے کہ مجھے راجیہ سبھا کی طرف سے حج کمیٹی کا ممبر نامی نیٹ کیا گیا تھا جس نے میں نے ۱۴ ارجون کو استعفیٰ دے دیا۔

میڈم، میں نے حج کمیٹی سے استعفیٰ دیتے وقت چیئرمین صاحب کو خط لکھا تھا۔ میں یہ امید کرتا تھا کہ حکومت۔ جو میں نے چیزیں اٹھائی ہیں۔ اس پر غور کرے گی۔

میڈم، اس سال حاجیوں کی جو درگتی بنی ہے مکہ میں۔ خاص طور پر وہ میں آپکے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھئے۔ حج کمیٹی ایک اہم ترین ادارہ ہے۔ جو ہندوستان کے ۲۵ ہزار حاجیوں کو یہاں سے لے جانے اور وہاں ان کے انتظامات کی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ اس میں ہر سال کچھ نہ کچھ کرپشن ہوتا رہا ہے۔ پچھلے تین سال سے میں بھی اس کا ممبر تھا اور پچھلے تین سال سے میں سعودی عرب برابر جا رہا تھا۔

میڈم، یہ بہت ہی سینسیٹو مذہبی مسئلہ ہے مسلمانوں کا اور میں اس کے لئے کوئی بات کہنے سے پہلے حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں نے پہلے بھی ایسا کیا ہے کہ آج تک ہندوستان میں جو بھی سرکار آئی ہے اس سرکار نے اس مسئلے کو ٹاپ پرائرٹی پر ... اس کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مکمل کوآپریشن دی ہے۔ میں اس موقع پر جو ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز آر۔ ایل۔ بھاٹیہ صاحب بیٹھے ہیں میں خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ ایک سال میں انہوں نے جو کوآپریشن حج کمیٹی اور حاجیوں کے لئے دی ہے۔ میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ میں نے گزشتہ اس سے دو سال پہلے اتنا کوآپریشن نہیں دیکھا۔

اس لئے جو آج میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں میری شکایت حکومت ہند سے نہیں ہے۔ مجھے سچی بات کہنی چاہیئے۔ کیوں کہ یہ بڑا مقدس فریضہ ہے۔ اس کے اندر میں کسی کو غلط بات نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ حج کمیٹی وہ ذمہ دار ادارہ ہے جو حاجیوں سے پیسے لے کر ان کو ہوائی جہاز سے لے جانے اور وہاں پر اکاموڈیشن کا انتظام کرتی ہے اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جب حاجی یہاں سے جاتے تو اس کو ہم حرم شریف سے یعنی ایکچول پلیس آف ورشپ جو وہاں ہے وہاں سے چار سو۔ آٹھ سو میٹر کی دوری پر رہنے کیلئے جگہ دیں۔

لیکن اس سال ایسے حالات پیدا ہوئے کہ کنٹریکٹ ایک پرائیویٹ پارٹی سے کیا گیا

[ ] Translation in Urbi.

اس سے پہلے یہ کانٹریکٹ سعودی عرب کا ایک ڈیپارٹمنٹ ہے موتس۔ اس کے ذریعے سے ہم وہاں اکوموڈیشن کا انتظام کرتے تھے۔

اس سال ہماری حج کمیٹی کا جو ڈیلیگیشن گیا اس نے کچھ حالات کی بنیاد پر ایک پرائیویٹ پارٹی سے کانٹریکٹ کیا۔ جب ہمارا حاجی یہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے دو مہینے بعد کانٹریکٹ کے۔ تو سعودی عرب گورنمنٹ سے ایک میسیج ہماری فارن منسٹری کو ملا کہ آپ کے حاجی پہنچنے سے پہلے۔ حج کمیٹی آئے اور ہم سے بات کرے۔ یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا۔ جس میں فارن منسٹری کے اور ایس۔ ڈی۔ حج بھی شامل تھے۔ میں بھی شامل تھا اور آج ایکس چیئرمین ہیں وہ بھی شامل تھے۔ ہم وہاں گئے۔ ہمیں سعودی منسٹر صاحب کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ ۴۔ اپریل کی بات ہے۔ انہوں نے ہم کو بتایا اور ۵۔ اپریل کو ہمارا شپ تقریباً ڈیڑھ ہزار حاجیوں کو لیکر کے وہاں پہنچنے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانٹریکٹ آپ نے الیگل کیا تھا ہے اور آپ کو کسی پرائیویٹ پارٹی سے یہ کانٹریکٹ کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کانٹریکٹ لینڈ لارڈ سے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن بیچ میں کسی پارٹی ایجنٹ کو لیکر کے یہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ میڈم، ہماری درخواست پر حج منسٹر نے انہوں کہہ دیا تھا کہ [illegible] لیکن ہم آٹھ کروڑ [illegible] پرائیویٹ پارٹی کو پے کر چکے تھے۔ اور دو حاجیوں کی [illegible] تھا۔ ہمارے پاس [illegible] اس آٹھ کروڑ کی بڑی فکر تھی۔ لہذا ہم نے حج منسٹر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں نے خود ہاتھ جوڑے اور یہ کہا کہ اگر یہ ہماری چانس غلطی ہوئی ہے۔ تو ہم کو موقع دیا جائے۔ ہمارا [illegible] ہم کیسے اس کو کر پائیں گے میں سعودی گورنمنٹ کو شکر گزار ہوں جو اس [illegible] صاحب کا [illegible] انہوں نے اس کے باوجود کہ [illegible] کیا اور ان کو آپریٹ کرنے کے ذریعہ حاجیوں کا انتظام کیا گیا اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈم، حاجیوں کو وہ انتظام اس سال ہم نہیں دے سکے۔ جو حاجی کا حق بنتا ہے۔ [illegible] ہزار روپے کی ایک خطیر رقم ادا کرتے وقت وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کام کے پیچھے کوئی غلط ارادہ ہے۔ میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی [illegible] کی بات کر رہا ہوں۔ میں کاؤنسل [illegible] کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ [illegible] ہے اور خاص طور سے ایکسپیڈ [illegible]

جو ہیں عشرت عزیز صاحب ...: مداخلت :...

اپ سبھاپتی: جو لوگ یہاں اپنے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ان کا نام مت لیجئے اور تھوڑا جلدی کیجئے۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میڈم، میں ایمبیسی کی بات کروں گا کہ اس نے وہ کوآپریشن نہیں دیا جو اس کا فرض بنتا تھا۔ اس کے نتیجہ میں حاجیوں کو سخت پریشانی ہوئی اور اس کے نتیجہ میں میں نے محسوس کیا کہ اس میں چاہے غلطی کسی کی بھی ہو ذمہ داری بنیادی طور پر حج کمیٹی کی ہے۔ چونکہ میں بھی حج کمیٹی کا ایک ممبر ہوں اور میڈم، اس سے زیادہ شرمناک بات حج کا معاملہ اور اخبار میں دلی کے اندر یہ چھپا اور اس کے بعد پورے ہندوستان کے اندر چھپا کہ حج کمیٹی کے کچھ لوگوں نے کروڑوں روپے کی رشوت ایکاموڈیشن کے اندر سے لی۔ میڈم، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حج کمیٹی کے کسی ممبر نے رشوت لی تھی تو کیا حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے۔ اس لئے کہ ہم ہر ایک ممبر ہیں۔ اگر میری حج کمیٹی کے کسی ممبر کے اوپر رشوت کا الزام لگتا ہے تو میں اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا۔ میں تو اسی دن جس دن یہ چھپے دن یہ اخبار میں خبر چھپی کہ حج کمیٹی کے کسی ممبر نے رشوت لی ہے۔ اگر یہ خبر جھوٹی تھی تو تب بھی میں استعفیٰ دے دیتا۔ لیکن میں نے اس لحاظ سے استعفیٰ نہیں دیا کہ اگر میں استعفیٰ دوں گا تو ایک ہیوک کریئیٹ ہو جائے گا۔ حاجیوں کا حجاز آنا شروع ہونے والا تھا۔ اگر میں اس وقت استعفیٰ دے دیتا تو ایک ہیوک کھڑا کریئیٹ ہو جاتا اور ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ حاجیوں کو بہت سخت پریشانی ہوتی۔ لہذا میں نے اس وقت اپنے آپ کو روکا۔ اور میں خود سعودی عرب اس بار گیا۔ جا کر کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حاجیوں کی دردشا دیکھی ہے، میڈم۔ آپ جانتی ہیں اچھی طرح سے کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی کمیونٹی سے ہے کہ ایک حاجی مکہ کے اندر کھڑے ہو کر کے کبھی کسی کو بددعا نہیں دے سکتا۔ ..: مداخلت :.. لیکن حرم شریف کے نیچے حاجیوں نے اس طرح کھڑے ہو کر حج کمیٹی کے ممبران کو بددعائیں دیں تو میں نے سوچا کہ میرا اس کمیٹی میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کمیٹی چاہے مکمل طور پر اس کے لئے ذمہ دار نہ ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسہ ہم لیتے ہیں حاجی سے، بیچارے غریب حاجی کو یہ پتہ نہیں کہ یہاں کیا پالیسی ہے، کس کی غلطی ہے، کون ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری

بنیادی طور پر حج کمیٹی کی ہے۔ اس لئے میں نے اپنا اخلاقی فریضہ سمجھا کہ اس سے استعفٰی دے دیا۔

پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے استعفٰی کا کیا ہوا۔ کیا میرا استعفٰی ایکسیپٹ ہوا یا نہیں۔ کیوں کہ کل دوبارہ حج کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ میڈم۔ دوسری بات۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے وزیر خارجہ کو ... "مداخلت" نہیں۔ میں بالکل نہیں ... "مداخلت"... میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ ڈیڈلاک ختم ہو گیا۔ "مداخلت"۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے .... "مداخلت"...

شری وشو جیت پرتھوی جیت سنگھ: پھر آپکو کل کی میٹنگ کی کیا پریشانی ہے۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: وشوجیت جی، میں کچھ بات اس سے ریلیٹڈ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ سن تو لیں۔

اپ سبھا پتی: افضل صاحب۔ آپ تھوڑا سنکشیپ میں بولیں تو مہربانی ہوگی۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میڈم میں ختم کر رہا ہوں۔ میں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی۔ دوسری جو پریشانی حاجیوں کو ہوئی وہ ائر لائنس کے سلسلے میں ہوئی تھی اس بار ائر انڈیا نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس جہاز نہیں ہیں۔ انڈین ائر لائنس نے ہمارے حاجیوں کو لے جانے سے انکار کر دیا اور ائر انڈیا کو انتہائی جلدی کے اندر ایرو فلوٹ سے کچھ ائر کرافٹ لیز پر لینے پڑے اور ان سے کانٹریکٹ کیا میڈم۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے۔ ہم ائر انڈیا کے سب سے بڑے کسٹمر ہیں یعنی حاجی۔ ہم ۴۳ کروڑ روپیہ کے ٹکٹ خریدتے ہیں۔ تو کیا یہ فارن ایکسچینج باہر جانا چاہیئے۔ کیا ائر انڈیا کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ سارا ٹریفک بجائے خود ہینڈل کرے۔ تاکہ یہ ہمارا پیسہ ملک میں موجود رہے آج ہم نے ایرو فلوٹ کو جو ٹکٹ کا پیسہ فارن ایکسچینج میں دیا کیا ضرورت تھی اسے باہر بھیجنے کی۔ اس لئے میں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی جب میں نے وزیر خارجہ کو یہ خط لکھا تھا کہ سول ایوی ایشن منسٹری کو وہ کہیں کہ وہ ایسا انتظام کریں کہ ہمارا نیشنل کیریئر خود حاجیوں کو لے کر جائے اور ہمارا فارن ایکسچینج ضائع نہ ہو۔ تیسری ڈیمانڈ میڈم میں نے یہ کی تھی کہ اس حج کمیٹی کو فوراً توڑ دیا جائے کیوں کہ اس حج کمیٹی کے اوپر عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اور میں استعفٰی اس لئے دیا ہے حالانکہ مجھے بھاٹیہ صاحب نے

मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश) : मैडम मैं अपने आपको इससे मुतालिक करता हूं ।

†[مولانا عبید اللہ خاں اعظمی :
میڈم - میں اپنے آپکو اس سے متعلق کرتا ہوں -]

उपसभापति : अफजल साहब, मैं आपको बतलाना चाहूंगी रिकार्ड के लिए कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है । आपने कहा कि आपका ताल्लुक है हज कमेटी से लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि मैं उस हज कमेटी की मेंबर नहीं हूं ।

श्री मोहम्मद अफज़ल उर्फ मीम अफज़ल : नहीं मैंने, यह नहीं कहा ।

†[شری محمد افضل عرف م- افضل :
نہیں میں نے یہ نہیں کہا -]

उपसभापति : नहीं, आपने कहा कि आप मेंबर हैं, मैं कोई मेंबर नहीं हूं उस हज कमेटी की ।

श्री मोहम्मद अफज़ल उर्फ मीम अफज़ल : मैडम, मैंने यह कहा कि आप जानती होंगी कि मक्के में पहुंचने के बाद कोई मुसलमान किसी को बददुआ नहीं देता है ।

†[شری محمد افضل عرف م- افضل :
میڈم - میں نے یہ کہا کہ آپ جانتی ہونگی کہ مکہ میں پہونچنے کے بعد کوئی مسلمان بد دعا نہیں دیتا ہے -]

†[ ] Transliteration in Arabic Script

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : मैडम, उन्होंने यह कहा कि आप उसी कम्यूनिटी को बिलांग करती हैं, इसे रिकार्ड से विद्ड्रा कर दिया जाना चाहिए ।

उपसभापति : नहीं, कम्यूनिटी नहीं कमेटी ।

Need for taking a Policy Decision to ensure adequate Funds to Narmada Project

श्री अन्नतराय देवशंकर दवे (गुजरात) : मैडम. मैं एक गंभीर मसले की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं जिसे कि मैंने पहले भी कई बार इस सदन में उठाया है। यह मामला नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में इसके संबंध में थोड़े दिनों से यहां दिल्ली में एक नाटक चल रहा था जोकि कल समाप्त हो गया है । बाबा आमटे ने दिल्ली में धरना दिया और कल उसे समाप्त कर दिया। मैडम, जब हम को वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि आपको हम ऋण नहीं देंगे और सरकार ने भी यह तय कर लिया कि हम वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं लेंगे, मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि वह अपनी पॉलिसी स्पष्ट करे कि वह यह पैसा कहां से लाएगी ? इस साल नर्मदा प्रोजेक्ट पर 12 सौ करोड़ रुपया खर्च करना तय हुआ है । 325 करोड़ रुपया गुजरात सरकार दे रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि 200 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है । मैं यह भी कहना चाहता हूं 30 जून तक 2509 करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च हो चुके हैं और 1200 करोड़ रुपया 1993–94 में खर्च होने वाला है। अब सरकार इन आंदोलनकारियों के दबाव में आकर डैम की हाइट रिव्यू करने का सोच रही है । मैडम, इस डैम से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान के लोगों को पीने के लिए और खेती के लिए पानी मिलने वाला है और मैं यह भी कह सकता हूं कि जब इस देश में भाखड़ा नंगल डैम बना तभी से जिस तरीके से गेहूं का उत्पादन बढ़ा और पंजाब का जिस तरीके से विकास हुआ उसके साथ मैं सारे देश की तरक्की होती जा रही है । इसी तरह यह नर्मदा प्रोजेक्ट अब केवल गुजरात का, महाराष्ट्र का या मध्यप्रदेश का प्रोजेक्ट नहीं रहा है, अब यह नेशनल प्रोजेक्ट है । मैडम, केन्द्रीय सरकार ने गौरव से कहा हैं कि हम वर्ल्ड बैंक के दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अपनी पॉलिसी यहां रखे कि यह पैसा वह कहां से लाएगी ? क्या वह लोन निकालेगी या कोई और रास्ता ढूंढेगी? हम तो कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए एन. आर. आई ज. बांड खरीदने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार की अभी 1.00 P.M. तक कोई पालिसी तय नहीं हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार का रवैया इस बारे में क्या है ?

दूसरी बात, महोदया. मैं यह कहना चाहता हूं कि आंदोलनकारियों के दबाव में आकर डैम की हाइट कम करना उचित नहीं है । यह चारों राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि देश के भी हित में नहीं है । हाईट कम नहीं होनी चाहिए । ट्रिब्युनल का यह जजमेंट है कि उनकी कोई भी चर्चा होगी या रिव्यू होगा तो वह 45 साल बाद होगा । यह आंदोलनकारी, थोड़े कुछ आंदोलनकारी कहीं विस्थापितों के नाम पर, कहीं एनवायरमेंट के नाम पर आंदोलन चलाते रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ दम नहीं है । सरकार के रवैये से आज गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान के लोगों को लग रहा है कि केन्द्र सरकार का इरादा गलत दिशा में जा रहा है क्योंकि यह आंदोलनकारी के साथ बैठने को तैयार हो गई है । हम चाहते हैं कि यदि आप विस्थापितों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो करें। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि विस्थापितों को जितना फायदा इस योजना की वजह से दिया गया है उतना सारी दुनियां में कहीं नहीं दिया गया है, कहीं दुनियां भर में नहीं दिया गया है । उन्हें जमीन दी है, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, रहने के लिए घरों की व्यवस्था की गई है ।

महोदया, केन्द्र सरकार का इरादा हमें अच्छा नहीं लग रहा है । इसी वजह से मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अपनी पालिसी तय करे कि वह क्या करना चाहती है और यहां हाउस में आकर बताए कि यह पैसा, संपूर्ण पैसा, जो 560 करोड़ रुपया इस साल में कम पड़ रहा है, वह किस तरीके से देगी, कब देगी ?

जो टाइम शेड्यूल नर्मदा योजना का बना है, उस योजना में कोई बाधा न पड़े, उसके लिए